ईरान द्वारा अमेरिका के युद्ध विराम को ठुकराने के बाद बदली स्थिति

क्रूड ऑयल के दामों में दोबारा तेजी

■ आने वाले दिनों में वैश्विक स्तर पर पड़ सकता है पेट्रोल-डीजल पर असर

आज समाज नेटवर्क

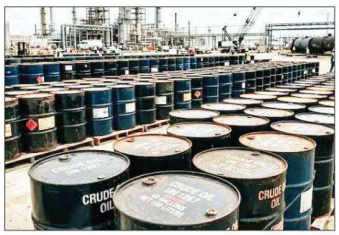

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गुरुवार को कच्चे तेल की कीमतों में फिर तेजी देखने को मिली। शुरूआती गिरावट के बाद कीमतों ने मजबूती पकड़ी, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव का रुख बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड 1.3 प्रतिशत बढ़कर 98.51 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। इससे एक दिन पहले बुधवार को यह 95 डॉलर प्रति बैरल से नीचे कारोबार कर रहा था। वहीं अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड की कीमत भी 1.6 प्रतिशत बढ़कर 91.75 डॉलर प्रति बैरल हो गई। ईरान ने ठुकराया युद्धविराम का प्रस्ताव तेल की कीमतों में यह वृद्धि ऐसे समय में हुई जब तेहरान ने बुधवार को अमेरिका द्वारा प्रस्तावित युद्धविराम योजना को खारिज कर दिया। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने ईरान को 15 सूत्री प्रस्ताव दिया था और ट्रम्प ने इस सप्ताह ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से अपने बिजली संयंत्रों को नष्ट करने की स्वयं निर्धारित समय सीमा को स्थगित कर दिया था। ईरान ने भी इस्राइल और खाड़ी अरब देशों पर और हमले शुरू कर दिए, जबकि इस्राइल ने तेहरान पर हवाई हमले किए और अमेरिका ने इस क्षेत्र में और अधिक अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने की तैयारी की। होर्मुज में बढ़ते तनाव से पड़ रहा असर ईरान और ओमान के बीच स्थित होर्मुज जलडमरूमध्य, जो कि एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है और जहां से दुनिया के लगभग पांचवें हिस्से के तेल का परिवहन होता है, ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से काफी हद तक बंद है। इसके चलते तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया है और युद्ध की शुरूआत से लेकर अब तक लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो अब अपने चौथे सप्ताह में है।

नायरा एनर्जी ने बढ़ाए पेट्रोल और डीजल के दाम

देश की सबसे बड़ी निजी ईंधन रिटेलर कंपनियों में शामिल नायरा एनर्जी ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। कंपनी ने पेट्रोल के दाम में पांच रुपये प्रति लीटर और डीजल में तीन रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। सूत्रों के अनुसार, यह फैसला वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हालिया तेजी के बाद लिया गया है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में तेज उछाल आया है, जिसका असर अब घरेलू बाजार पर भी दिखने लगा है। अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में हुई करीब 50% की बढ़ोतरी बताया जा रहा है कि 28 फरवरी के बाद से अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में करीब 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। इसी दौरान भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें लंबे समय से स्थिर बनी हुई थीं, जिससे ईंधन विपणन कंपनियों पर लागत का दबाव बढ़ रहा था।

देश के 6,967 पेट्रोल पंपों पर कंपनी का संचालन

नायरा एनर्जी देश के कुल 1,02,075 पेट्रोल पंपों में से करीब 6,967 पंप संचालित करती है। कंपनी ने अब बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा उपभोक्ताओं पर डालने का फैसला किया है। हालांकि, इस मुद्दे पर कंपनी की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया फिलहाल सामने नहीं आई है। सूत्रों के अनुसार, रूस की रोसनेफ्ट के स्वामित्व वाली नायरा ने पेट्रोल की कीमत में पांच रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में तीन रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है, लेकिन प्रभावी वृद्धि दर राज्यों के अनुसार अलग-अलग है, जो वैट जैसे स्थानीय करों पर निर्भर करती है। कुछ स्थानों पर पेट्रोल की कीमत में 5.30 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। क्या है दूसरी कंपनियों का हाल? वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज और बीपी की संयुक्त कंपनी जियो-बीपी ने अब तक कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि उसे पेट्रोल-डीजल बिक्री पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी ओर, सरकारी तेल

सिलाव की मंजुला ने 'पीएमएफएमई' योजना से खड़ा किया 10 लाख का मसाला उद्योग, 30 से अधिक लोगों को दिया रोजगार

आज समाज नेटवर्क

नालंदा। कभी छोटे स्तर पर हल्दी पीसकर लोकल मार्केट में बेचने वाली बिहार में स्थित सिलाव प्रखंड के सरीचक गांव की मंजुला कुमारी आज इलाके की महिलाओं के लिए मिसाल बन गई हैं। 'पीएमएफएमई' योजना की मदद से उन्होंने न सिर्फ अपने गांव के नाम पर 'सरीचक एंटरप्राइजेज' नामक मसाला उद्योग खड़ा किया है, बल्कि 30 से अधिक लोगों को रोजगार देकर स्वावलंबन की नई कहानी लिख दी है। मंजुला ने बाजार में मिलने वाले आम मसालों से अलग, गुणवत्ता और शुद्धता पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। उनकी यूनिट में हल्दी, मिर्च, धनिया और गरम मसाले पीसने के लिए अलग-अलग मशीनें लगी हैं। आज वे शुद्ध मसाले सिलाव के गांवों से निकलकर राजगीर के नामी होटलों और मॉल तक अपनी महक बिखेर रही हैं। मंजुला ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि वह पहले से ही हल्दी का छोटा व्यवसाय करती थीं, लेकिन मांग पूरी नहीं कर पा रही थीं। इसी बीच जीविका के माध्यम से उन्हें सरकार की पीएमएफएमई (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन) योजना की जानकारी मिली। बड़े स्तर पर व्यवसाय शुरू करने की सोच के साथ उन्होंने आवेदन किया और बड़गांव स्थित केनरा बैंक से उन्हें 7 लाख 21 हजार रुपये का लोन मिल गया। अपनी जमा-पूंजी मिलाकर करीब 10 लाख रुपए की लागत से उन्होंने अपनी यूनिट लगाई। उन्होंने बताया, "आमतौर पर लोग एक ही मशीन में सारे मसाले पीस देते हैं, लेकिन हमारी हल्दी की मशीन बिल्कुल अलग है। उसमें सिर्फ हल्दी ही पीसी जाती है, ताकि ग्राहकों को शत-प्रतिशत शुद्धता मिल सके। हमारे यहां खड़ा और पिसा हुआ, दोनों तरह का मसाला तैयार होता है।

खबर एक्सप्रेस

रिलायंस टेलीकॉम एसबीआई फ्रॉड केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, मुंबई में कई ठिकानों पर की छापेमारी

मुंबई। रिलायंस टेलीकॉम एसबीआई फ्रॉड केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने देश की आर्थिक राजधानी में इस मामले से जुड़ी कंपनी और लोगों के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें सतीश सेठ और गौतम दोशी के आवास के साथ-साथ कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस भी शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक, इस दौरान लोन ट्रांजैक्शन और वित्तीय लेन-देन से जुड़े कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एजेंसी अब बैंकिंग रिकॉर्ड, आपसी पत्राचार और लोन मंजूरी से जुड़े आंतरिक दस्तावेजों की जांच करेगी। जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि तलाशी अभियान अभी जारी है और जांच के दौरान और सबूत जुटाए जा सकते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और उसके पूर्व निदेशकों सतीश सेठ और गौतम बी. दोशी समेत कुछ अज्ञात सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज किया है। यह मामला भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से जुड़े करीब 114.98 करोड़ रुपए के कथित घोटाले से संबंधित है। अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत आपराधिक कदाचार और पद के दुरुपयोग से जुड़े प्रावधान भी लगाए गए हैं। यह मामला एसबीआई की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि संबंधित कंपनियों और व्यक्तियों ने बैंक के साथ धोखाधड़ी की, जिससे उसे भारी वित्तीय नुकसान हुआ। एसबीआई उन 11 बैंकों के कंसोर्टियम का हिस्सा था, जिन्होंने मिलकर रिलायंस टेलीकॉम को 735 करोड़ रुपए का टर्म लोन दिया था। केस दर्ज करने के बाद सीबीआई ने मुंबई में कई स्थानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई रिलायंस ग्रुप से जुड़ी कंपनियों में कथित वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के बीच की जा रही है। इससे पहले इसी महीने सीबीआई ने अनिल अंबानी से एक अलग मामले में पूछताछ की थी। यह मामला रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) से जुड़े लगभग 2,929 करोड़ रुपए के कथित बैंक धोखाधड़ी से संबंधित था, जिसकी शिकायत भी एसबीआई ने की थी। अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में लोन की राशि के गलत इस्तेमाल और तय शर्तों के उल्लंघन के आरोप हैं।

भारत में वित्त वर्ष 2026 में क्रेडिट ग्रोथ 61 प्रतिशत बढ़ी, रिटेल और एमएसएमई से मिली मजबूती: रिपोर्ट

नई दिल्ली। भारत में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान क्रेडिट ग्रोथ में बड़ा उछाल देखने को मिला है। गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में कर्ज (लोन) की वृद्धि 61 प्रतिशत बढ़ी है, जिसमें रिटेल ग्राहकों और एमएसएमई सेक्टर की मजबूत मांग का बड़ा योगदान रहा है। यस बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026 में कुल क्रेडिट फ्लो बढ़कर 25.1 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो लगभग 26.1 लाख करोड़ रुपए की जमा (डिपॉजिट) के बराबर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रिटेल, एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मजबूत मांग इस बढ़त की मुख्य वजह रही है। हालांकि, वित्त वर्ष 2024 से डिपॉजिट ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ रही है, जिससे बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी पर थोड़ा दबाव बन रहा है। इसी कारण क्रेडिट-डिपॉजिट (सी/डी) रेशियो बढ़कर 82.4 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जो पिछले 10 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। रिटेल लोन इस ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। पर्सनल लोन की हिस्सेदारी 29 प्रतिशत से बढ़कर 33 प्रतिशत हो गई है। टैक्स में राहत और जीएसटी से जुड़े फायदे के कारण लोगों की आय बढ़ी है, जिससे लोन लेने की क्षमता भी बढ़ी है। इस सेगमेंट में वाहन लोन सबसे बड़ा ड्राइवर बनकर उभरा है, जिसने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही से हाउसिंग लोन को भी पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट में यह भी देखा गया है कि अब लोग सुरक्षित लोन की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, जबकि बिना गारंटी वाले लोन की ग्रोथ धीमी हो गई है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट में भी सुधार देखने को मिला है, जिसमें एमएसएमई सेक्टर की बड़ी भूमिका रही है। अब यह सेक्टर कुल औद्योगिक कर्ज का लगभग एक-तिहाई हिस्सा बन चुका है। सरकार की योजनाओं, जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम और एमएसएमई की नई परिभाषा, ने इस ग्रोथ को बढ़ावा दिया है। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज ने इस साल 2.38 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जोड़ा, जबकि मीडियम एंटरप्राइज ने 63,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया। हालांकि, रिपोर्ट में आगे के लिए सावधानी भी जताई गई है।

भारत में कमर्शियल ड्रोन बाजार में तेजी, 2029 तक 18 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान : रिपोर्ट

मंबई। भारत में कमर्शियल ड्रोन इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में इस सेक्टर का बाजार आकार 1.88 अरब डॉलर (करीब 17,000 करोड़ रुपए) तक पहुंच चुका है। अब अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2029 के बीच यह बाजार करीब 17.98 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ेगा। रिसर्च फर्म बीटूके एनालिटिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर कमर्शियल ड्रोन इंडस्ट्री में अमेरिका पहले स्थान पर है, उसके बाद चीन का नंबर आता है जबकि भारत फिलहाल सातवें स्थान पर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ड्रोन तकनीक खेती में लागत कम करने का बड़ा जरिया बन रही है। खासकर एग्रोकेमिकल छिड़काव में ड्रोन के इस्तेमाल से लागत लगभग 80 प्रतिशत तक कम हो सकती है। एक अध्ययन में 6.4 से 7.1 लाख रुपए कीमत वाले छोटे और मध्यम ड्रोन का विश्लेषण किया गया, जिनकी अधिकतम कार्य अवधि तीन साल मानी गई। इसकी तुलना में, मैनुअल मजदूरी पर सालाना करीब 1.7 लाख रुपए खर्च होते हैं। हालांकि ड्रोन की शुरूआती लागत ज्यादा होती है, लेकिन उनकी कार्यक्षमता कहीं अधिक है। ड्रोन उतने समय में 6 से 6.6 एकड़ जमीन पर काम कर सकते हैं, जितना समय मजदूर एक एकड़ में लगाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, दक्षता और लागत को मिलाकर देखें तो ड्रोन मैनुअल श्रम के मुकाबले 78 प्रतिशत से ज्यादा किफायती साबित होते हैं। भारत में इस समय 122 ड्रोन मॉडल्स को टाइप सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जो कि डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) द्वारा जारी किया जाता है। यह प्रमाणन इस बात की पुष्टि करता है कि ड्रोन सुरक्षा, उड़ान क्षमता और प्रदर्शन के मानकों पर खरे उतरते हैं। इनमें से करीब 70 प्रतिशत ड्रोन कृषि कार्यों, खासकर छिड़काव के लिए उपयोग हो रहे हैं। वहीं, 24 प्रतिशत ड्रोन सर्विलांस और मैपिंग जैसे कामों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इससे साफ है कि फिलहाल भारत में ड्रोन का सबसे बड़ा उपयोग खेती में हो रहा है। सरकार की नीतियों ने भी इस सेक्टर को बढ़ावा दिया है। पूरी तरह तैयार ड्रोन के आयात पर रोक और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ने स्थानीय निर्माण और रिसर्च को मजबूती दी है।

सेबी ने गूगल के साथ मिलकर वेरिफाइड बैज की लॉन्च

आज समाज नेटवर्क

नई दिल्ली। शेयर बाजार में तेजी से बढ़ती खुदरा निवेशकों की भागीदारी के बीच फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स एक बड़ा जोखिम बनकर उभरे हैं। इस बढ़ते खतरे को रोकने और निवेशकों की गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखने के लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने बुधवार को एक अहम कदम उठाया है। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने फर्जी एप्लीकेशंस को एक गंभीर खतरा करार देते हुए गूगल के साथ मिलकर एक नई वेरिफाइड एप लेबल शुरू करने का एलान किया। बाजार का विस्तार और सुरक्षा की जरूरत बुधवार को मुंबई में आयोजित इस कार्यक्रम में सेबी प्रमुख ने बताया कि भारत में अब 'यूनिक' निवेशकों की संख्या 14 करोड़ के आंकड़े को छू चुकी है। इसके साथ ही शेयर बाजार का कुल बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) भी 423 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है। निवेशकों की अगली बड़ी लहर के जल्द आने की उम्मीद जताते हुए उन्होंने बाजार के सभी हितधारकों के भरोसे को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। पांडे ने स्पष्ट किया कि फर्जी ऐप्स निवेशकों को अपूरणीय वित्तीय नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए सेबी का दृष्टिकोण नुकसान होने से पहले ही सुरक्षा उपाय लागू करने का है। क्या है 'वेरिफाइड बैज' पहल? इस नई पहल के तहत, गूगल के प्ले स्टोर पर मौजूद असली और सुरक्षित ऐप्स पर एक 'वेरिफाइड बैज' दिखाई देगा। इस बैज को देखकर उपयोगकर्ता सुरक्षित रूप से लेनदेन कर सकेंगे। शुरूआती चरणः इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत स्टॉक ब्रोकर्स के 600 ऐप्स के साथ की जा रही है।

सोने की रिफाइनिंग और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने की जरूरत : रिपोर्ट

आज समाज नेटवर्क

नई दिल्ली। भारत का स्वर्ण (गोल्ड) क्षेत्र इस समय बड़े संरचनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जहां मांग का स्वरूप खपत आधारित से निवेश आधारित होता जा रहा है। आईसीआरए और एसोचैम की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, देश में घरेलू खनन उत्पादन बेहद कम होने के कारण भारत अब भी सोने के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। रिपोर्ट में इस निर्भरता को कम करने के लिए संगठित रिफाइनिंग और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया गया है। साथ ही, गोल्ड डोरे (कच्चा सोना) पर कम आयात शुल्क बनाए रखने और IGDS मानकों वाले बार्स को व्यापक स्वीकार्यता देने की सिफारिश की गई है, ताकि घरेलू रिफाइनर वित्तीय बाजारों से बेहतर जुड़ सकें। इसके अलावा, गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम (GMS) को फिर से प्रभावी बनाने की जरूरत बताई गई है, क्योंकि शुरूआत से ही इसमें सीमित भागीदारी देखने को मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक, भावनात्मक जुड़ाव और पारंपरिक सोच के कारण लोग अपने आभूषण इस योजना में शामिल करने से हिचकते हैं। रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि योजना को सरल बनाया जाए, इसके लाभों के बारे में बेहतर जानकारी दी जाए और संगठित ज्वैलर्स को इस प्रक्रिया में शामिल कर लोगों का भरोसा बढ़ाया जाए, ताकि देश में मौजूद निष्क्रिय सोने को आर्थिक रूप से उपयोग में लाया जा सके। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच ऑफिस स्पेस की मांग मजबूत, लीजिंग में 15% उछाल वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद देश के प्रमुख शहरों में ऑफिस स्पेस की मांग मजबूत बनी हुई है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट कोलियर्स के अनुसार, जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान सात बड़े शहरों में कुल ऑफिस स्पेस लीजिंग 15 प्रतिशत बढ़कर 18.3 मिलियन वर्ग फुट हो गई। यह आंकड़ा पिछले साल की समान अवधि के 15.9 मिलियन वर्ग फुट से अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह वृद्धि बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे जैसे प्रमुख बाजारों में देखने को मिली। कोलियर्स ने कहा कि विभिन्न सेक्टरों से बढ़ती मांग और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) के विस्तार ने इस तेजी को सहारा दिया है, जबकि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। देश के सबसे बड़े ऑफिस मार्केट बेंगलुरु में लीजिंग गतिविधि में खासा उछाल देखने को मिला।

तेलंगाना में निवेश की बड़ी छलांग, दावोस से 2.19 लाख करोड़ के 44 समझौते

तेलंगाना सरकार ने वैश्विक निवेश आकर्षित करने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। राज्य के उद्योग मंत्री श्रीधर बाबू ने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की 2024 और 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (दावोस) यात्राओं के दौरान कुल 44 समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए, जिनकी कुल निवेश राशि 2.19 लाख करोड़ रुपये है। मंत्री ने कहा कि ये सभी निवेश प्रस्ताव फिलहाल विभिन्न चरणों में लागू हो रहे हैं और इनसे राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं के माध्यम से करीब 68,150 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि राज्य सरकार ने भूमि आवंटन के जरिए अब तक 1,540 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। सरकार का फोकस निवेश को जमीन पर उतारने और रोजगार सृजन को गति देने पर है, ताकि तेलंगाना को प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में और मजबूत किया जा सके।

खुदरा महंगाई को लेकर केंद्र सरकार ने रखा पांच साल का लक्ष्य

आज समाज नेटवर्क

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए खुदरा महंगाई (रिटेल इन्फ्लेशन) का लक्ष्य चार प्रतिशत पर यथावत रखने का निर्णय लिया है। यह लक्ष्य 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगा। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने 25 मार्च 2026 को जारी अधिसूचना में इसकी जानकारी दी। अधिसूचना के अनुसार, महंगाई के लिए 4 प्रतिशत का लक्ष्य तय किया गया है, जबकि इसकी ऊपरी सहनशील सीमा 6 प्रतिशत और निचली सीमा 2 प्रतिशत रखी गई है। यह निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45इअ के तहत, रिजर्व बैंक के परामर्श से लिया गया है।

एमपीसी के फैसले पर पड़ेगा असर सरकार के इस फैसले के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का मौजूदा जनादेश भी बरकरार रहेगा। मौद्रिक नीति समिति (MPC) अब भी इसी लक्ष्य के अनुरूप नीतिगत ब्याज दरों का निर्धारण करेगी, ताकि महंगाई को निर्धारित दायरे में रखा जा सके। गौरतलब है कि भारत ने 2016 में औपचारिक रूप से महंगाई लक्ष्य निर्धारण (इन्फ्लेशन टार्गेटिंग) का ढांचा अपनाया था।

उसी समय एमपीसी का गठन हुआ था, जिसे मूल्य स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। शुरूआती अवधि मार्च 2021 तक थी, जिसके बाद सरकार ने इस लक्ष्य को लगातार जारी रखा है। यह दूसरा अवसर है जब सरकार ने बिना बदलाव के चार प्रतिशत लक्ष्य को आगे बढ़ाया है। मौजूदा महंगाई की स्थिति फरवरी 2026 में CPI आधारित महंगाईः 3.21% ग्रामीण महंगाईः 3.37% शहरी महंगाईः 3.02% खाद्य महंगाई (CFPI): 3.47% यानी महंगाई फिलहाल लक्ष्य (4%) से नीचे है। इस दौरान टमाटर, मटर और फूलगोभी जैसी सब्जियों की कीमतों में 10 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई, जिससे खाद्य महंगाई पर दबाव कम हुआ।

किन राज्यों में महंगाई ज्यादा? फरवरी 2026 में सबसे ज्यादा महंगाई वाले राज्यः तेलंगाना राजस्थान केरल आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल कैसे जुटाया जाते हैं आंकड़े? सरकार के अनुसार, महंगाई के आंकड़े देशभर के 1407 शहरी बाजारों और 1465 गांवों से एकत्र किए जाते हैं।

एशियाई बाजारों में निवेशकों का सतर्क रुख

आज समाज नेटवर्क

नई दिल्ली। एशियाई शेयर बाजारों में गुरुवार को ज्यादातर गिरावट दर्ज की गई, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त देखने को मिली। निवेशकों के बीच सतर्कता का माहौल बना हुआ है, क्योंकि ईरान से जुड़े युद्ध में तनाव कम होने को लेकर अभी भी स्पष्टता नहीं है। टोक्यो का निक्केई 225 सूचकांक 0.3 प्रतिशत गिरकर 53,607.75 पर कारोबार कर रहा था। दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 1.9 प्रतिशत गिरकर 5,537.30 पर आ गया। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 1.4 प्रतिशत गिरकर 24,978.71 पर आ गया। शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.6 प्रतिशत गिरकर 3,909.16 पर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 इंडेक्स 0.2 प्रतिशत नीचे गिर गया। ताइवान का ताइएक्स इंडेक्स 0.4 प्रतिशत ऊपर कारोबार कर रहा था। क्या रहा अमेरिकी बाजार का हाल? बुधवार को वॉल स्ट्रीट के शेयर बाजार में तेजी के साथ कारोबार समाप्त हुआ। एसएंडपी 500 में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 6,591.90 पर पहुंच गया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 46,429.49 पर पहुंच गया, जबकि नैस्डैक कंपोजिट में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 21,929.83 पर बंद हुआ। अमेरिकी वायदा बाजार में 0.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। तेल की कीमतों में आया 1.3% का उछाल गुरुवार को तेल की कीमतों में शुरूआती गिरावट के बाद फिर से उछाल आया। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 1.3 प्रतिशत बढ़कर 98.51 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गया। बुधवार को यह 95 अमेरिकी डॉलर से नीचे था। अमेरिकी मानक क्रूड 1.6 प्रतिशत बढ़कर 91.75 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में दिखी सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट गुरुवार की सुबह बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सोने की कीमत 0.8 प्रतिशत गिरकर 4,513.90 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस हो गई। चांदी की कीमत में 0.9 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 71.97 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर आ गई। अमेरिकी डॉलर 159.47 जापानी येन से गिरकर 159.42 जापानी येन पर आ गया।

पश्चिम एशिया तनाव से आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई : गोयल

■ कहा, इस वैश्विक चुनौती से एकजुटता से निपटना होगा

आज समाज नेटवर्क

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया संकट से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए देश को एकजुट होना होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार यह बात कही। अमेरिका और इस्राइल की ओर से ईरान पर किए गए संयुक्त हमले ने जहाजों की आवाजाही को बाधित कर दिया है और वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है। गोयल ने कहा, 'युद्ध चल रहा है, हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है। भारत किसी भी तरह से युद्ध में शामिल नहीं है। लेकिन जब युद्ध चल रहा होता है, तो नुकसान तो होता ही है, मुश्किलें भी आती हैं, हो सकता है कि मालाबार को मध्य पूर्व के देशों में निर्यात करने में कठिनाई हो रही हो।

लेकिन यही वह समय है जब राष्ट्र को एकजुट होना होगा। राष्ट्र को मिलकर इस दौर की चुनौतियों का सामना करना होगा।' उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने 38 विकसित देशों को शामिल करने वाले नौ क्षेत्रों के साथ नौ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि ये समझौते वैश्विक व्यापार के लगभग दो-तिहाई हिस्से तक तरजीही बाजार पहुंच प्रदान करते हैं और इस बात पर जोर दिया कि भारतीय उद्योग, किसानों, लघु एवं मध्यम उद्यमों और कारीगरों को गुणवत्ता पर मजबूत ध्यान केंद्रित करके इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मालाबार चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 2026-27 के लिए राष्ट्रीय सीएसआर घोषणा और छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम के शुभारंभ को संबोधित कर रहे थे।

MANAPPURAM FINANCE LTD.

CIN: L65910KL1992PLC006623,
Registered Office : W - 4/ 638A, Manappuram House, P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16.04.2026 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :

कुरुक्षेत्र, 127270700016075

ऊपर बताई गई नीलामी में हिस्सा लेने के इच्छुक व्यक्तियों को नीचे दी गई बातों का पालन करना होगा: इच्छुक बोली लगाने वालों को नीलामी के दिन ही एनईएफटी/आरटीजीएस के ज़रिए 10,000/- रुपये ईएमडी (जो बोली हारने वालों को वापस कर दिया जाएगा) जमा करना होगा। बोली लगाने वालों के पास वैध आईडी कार्ड/पैन कार्ड होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया 9072607147 पर संपर्क करें।

अधिकृत अधिकारी
मणप्पुरम फायनेंस लि. हेतु.